200

DECEMBER 12, 1980

(c) the further steps Government propose to take to help the educated unemployed in the backward district of Orissa?

MINISTER OF FINANCE THE (SHRI R. VENKATARAMAN): (a) and (b). All public sector banks have been endeavouring to create selfemployment opportunities for the unemployed—both educated and uncredit educated—through increased deployment in the priority sectors of small industry, agriculture, small transport, retail trade and small business, professional and self-employed etc. The data reporting system, however, does not yield information regarding credit assistance by banks to educated unemployed as a separate The total number of category. borrowal accounts financed by the public sector banks in the priority sectors, which gives an indication of the increasing assistance flowing for self-employment ventures in Orissa, increased from 2.30 lakhs in December, 1977 to 3.20 lakhs in December. 1978 and further to 4.04 lakhs in December, 1979. The outstanding credit was of the order of Rs. 51 crores, Rs. 73 crores and Rs. 102 crores respectively.

(c) Banks have been endeavouring to facilitate the flow of credit to the small borrowers through simplification of their lending procedures, quick disposal of applications, relaxation requirements of margins and security etc. District Credit Plans have been drawn up for all the lead districts also keeping in view the employment generation aspect of credit deployment. Recently, the public sector banks have been advised that by 1985 their priority sector advances should reach 40 per cent of their aggregate advances. It is expected that implementation of these measures will help the unemployed to take up an increasing number of self employment ventures in all the districts of Orissa as also of other States.

Levil and Zinc Deposits Fund in Rampura-Agucha Beit in Rajasthan

3659. SHRI MANPHOOL SINGH CHAUDHARY: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that large lead and zinc deposits have recently come to light at Rampura-Agucha belt in Rajasthan;
- (b) whether any detailed exploration is proposed of the belt; and
 - (c) the details thereof?

COMMERCE THE MINISTER OF MINES STEEL AND AND (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) to (c). Yes, Sir. During the year 1979, Directorate of Mines and Geology. Government of Rajasthan, discovered a Lead-Zinc Prospect near Rampura-Agucha, District Bhilwara (Rajasthan). After completion of preliminary geological investigations, the Directorate of Mines and Geology commenced Surface Diamond Drilling and intersected rich lead-zinc mineralisation about 60 metres wide with metal content of about 10 per cent Zinc and Lead.

The preliminary evaluation indicates that the prospect may have reserve potential of an order of about 35 million tonnes containing over 10 per cent zinc and lead upto 285 m. depth for over 1400 metres strike length. Hindustan Zinc Limited has received Mining Lease over an area of 12 sq. kms. The company has started detailed exploration of this prospect since February, 1980, and the work is in progress.

मृतक जमाकर्तामां के उत्तराधिकारियां व्वारा पूरी की जाने वाली औपचारिकताएं

3660. **श्री अज्ञोक गहलातः क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मालूम है कि मृत व्यक्तियों के बचत बँक खाते में जमा धनराशि वापस करते समय राष्ट्रीयकृत बँक उनके उत्तराधिकारियों से कठिन औपचारिक-तायों पूरी करने का आग्रह करते हैं; और

विस मंत्री (श्री आर. वंकटरामन): (क) और (स). सरकार द्वारा वर्ष 1975 में, बैंकों में ग्राहक सेवा विषयक एक कार्यकारी द्भल नियुक्त किया गया था, जिसने यह सिफारिश की थी कि मृतकों के उत्तरा-रिधकारियों/दावाकर्ताओं को मृतक-साता में पड़ी शेष जमा राशि की अदायगी, वैधु प्रमाणपत्र प्रस्तृत किए बिना, परन्तू उपयुक्त स्थानीय जांच तथा पर्याप्त क्षतिपृत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर की जाए। इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए सरकारी क्षेत्र को दोंकों को पहले ही कहा जा चुका है। लेकिन दावाकर्ताओं द्वारा पूरी की जाने वाली औपचारिकताएं तथा इस प्रकार के किस हद तक के दावों को शासा प्रबन्धकों द्यारा निपटाने की शक्तियां, अलग अलग बेंकों पर छोड दी गयी थीं । सामान्यतः इस प्रकार के 5000 रुपये तक के दानों निपटाने का अधिकार शासा प्रबन्धकों में निहित है। इस सम्बन्ध में पूरी की जाने वाली औपचारिकताओं में भी एक बैंक से दूसरे बैंक में भिनाता है, लेकिन कुल मिलाकर सरकारी क्षेत्र के वैंक निम्नलिखित अपिचारिकताओं में से एक अथवा अधिक को लिए जोर दोते हैं:

- 1) मृत्यु प्रमाणपत्र;
- 2) अदायगी के लिए आवेदन पत्र;
- 3) अर्न्तप्रस्त राशिकी अदायगी किए जाने के सम्बन्ध में किसी दावा, मांग, कार्यवाहियों, हानियों तथा न्कसानों के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करने को बार में जमानतदारों के साथ किये गए क्षतिपृति सम्बन्धी करार;
- 4) उन व्यक्तियों से घोषणापत्र जिनको बैंक जानता हा;
- 5) दो ऐसे मान्य व्यक्तियों द्वारा दिए गए शपथपत्र जिन्हें मतक का परिवार

जानता हो और उक्त शपथपत्र, निटरी पव्लिक अथवा न्यायाधीश द्वारा सत्यापित किया गया हा:

- 6) सभी उत्तराधिकारियों दवारा हस्ता-क्षरित अधित्यागपत्र :
- 7) सम्बन्धित पास बुक/अप्रयुक्त चेक फार्म ।

जिन मामलों में दावदारों द्वारा उत्तरा-धिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए जाते उनमें उपयुक्ति सूचीवद्ध औपचारिकताएं पूर्ववती शतों के रूप में आवश्यक हैं। इन गरैपचारिकताओं को पूरा करने में कोई ज्यादा सर्च नहीं लगता क्योंकि ये कागजात या तो सादे कागज पर अथवा कर खचीले स्टाम्प वाले कागज पर तैयार करने पड़ते हुई भविष्य में किन्हीं प्रतिदावों के सम्बन्ध में देंकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये कागजात आवश्यक समभो जाते हैं।

भारतीय स्टोट बींक की फतेहपुरी स्थित शासा में मृत व्यक्तियों के बचत बैंक खाते

- 3661. श्री अज्ञोक गहस्रोतः विस्त मंत्री यह बताने की कृपा करोंगे कि:
- (क) मत व्यक्तियों के उन बचत दैंक खातों की संख्या कितनी है जो भारतीय स्टोट बैंक की फतहपूरी स्थित शासा में अभी तक अनिर्णीत पड़े हैं:
- (स) क्या उक्त शासा के दैंक मैनेजर को एसे खाताधारियों के उत्तराधिकारियों को ध्न का भगतान करने की विशेष शक्तियां प्रदान की गई है;
- (ग) यदि हां, तो इन विशेष शक्तियाँ के अधीन कितनी राशि निद्याली जा गकती ਰ ੈ;
- (घ) उन साताधारियों का ब्यौरा क्या है जिनके उत्तराधिकारियों को बैंक मैनेजर दवारा इस प्रयोजन के लिये उसे दी गई विशेष शक्तियों के अन्तर्गत उस धन वापसी की जा सकती है;